AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) In the context of large spinning capacity already created in the country, the financial institutions have not been in favour of financing new spinning mills. The Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that one case by case review on merits of 11 unimplemented projects in the cooperative sector in Maharashtra, it has already sanctioned assistance in one case and has taken up another application for processing. In accordance with the provisions of Section 29 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964, information relating to or to the affairs of its constituents cannot be divulged except in circumstances, in which it is, in accordance with law or practice and usage, customary among bankers, necessary or appropriate for IDBI to divulge such information.

Project from Andhra Pradesh pending clearance

203. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) how many projects submitted by Andhra Pradesh Government are pending at present for clearance from environmental and forest angles;

(b) what are the details of objections to their celarance; and

(c) what steps are being taken by the Central Government to settle these issues amicably with the State Government?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) The details of proposals received from Andhra Pradesh, pending clearance from environmental and forest angles are given in the Annexure [*See* Appendix CXLVIII, Annexure No. 6].

(c) In most of the cases are shown in the Annexures the proposals are pending for want of certain information and the State Government has been requested to furnish the same. The decisions on these proposal can be taken as and when the complete details are furnished by the State Government. In the remaining cases which are under process in the Ministry, decisions will be taken soon.

दिल्ली पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी

204. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस विभाग में जिन नागरिकों की "विशेष पुलिस अधिकारी" के रूप में नियुक्ति की जाती है उन्हें मंत्रालय द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा कोई सुरक्षा अथवा अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जबकि अन्य मंत्रालयों द्वारा सलाहकार समितियों को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त "विशेष पुलिस अधिकारियों" को टेलीफोन और सुरक्षा संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और अन्य ड्यूटियों के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत जनता में से पूर्णत: स्वयंसेवी आधार पर विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) विशेष पुलिस अधिकारी अवैतनिक और पुलिस की सहायता करने के लिए स्वयंसेवी कार्यकर्ता होते हैं। सरकारी खर्च पर कोई वस्तु-पूरक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं।

Central Assistance to Bihar to improve economic conditions in Naxalite-Infested areas

205. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government have agreed to provide financial assistance to the Bihar Government to implement schemes aimed at improving the economic conditions in the naxalite-infested areas in the State;

(b) if so, the quantum of assistance promised;

(c) the details of the schemes proposed to be implemented in this connection; and

(d) whether the Central Government would sanction ad-hoc assistance to the State Governmemnt for better implementation of the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The Planning Commission has already finalised the Five Year Plan for Bihar giving utmost consideration to its economic backwardness within the approved formula of Central assistance. Further an action plan to curb the Naxal and caste violence covering the three highly infested districts of Jahanabad, Aurangabad and Gaya has been prepared. A detailed programme of development of these three districts has been drawn up involving an additional lay out of Rs. 26 crores of which Rs 10 crores are to be provided by the Central Government and the remaining to be mobalised by the State Government. The development plan covers land reform, distribution of surplus land and minor irrigation etc.

राजभाषा अधिनियम की रजत जयन्ती

206. **डा० रत्नाकर पाण्डेय**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1988-89 का वर्ष राजभाषा अधिनियम का रजत जयंती वर्ष है और क्या विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस रजत जयंती वर्ष को बनाये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है,; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 को पारित किए हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। इस अधिनियम की रजत जयंती मनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) संसद द्वारा अनेकों अधिनियम पारित किए गए हैं। उनकी रजत जयंती मनाने की प्रणाली नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी के सिलसिलें में राजभाषा विभाग की ओर से एक राजभाषा सम्मेलन का आयोजन इसी वर्ष किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। इसलिए राजभाषा अधिनियम की रजत जयंती मनाने की विशेष आवश्यकता नहीं।

हिन्दी सलाहकार समितियां

207. **डा० रत्नाकर पांडेय**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन किन-किन मंत्रालयों में अभी तक हिंदी सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया गया है;